(c) have these plans been discussed at any significant level with the States; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

बाण सागर परियोजना

1852. **श्री मनोहर कान्ता ध्यानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोन नदी से संबंधित "बाण साग्रर परियोजना" उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य त्रिपक्षीय सहमति से वर्ष, 1973 में शुरू की गई थी;

(ख) क्या नदी-जल के बंटवारे के लिए कोई आयोग बनाया गया था और क्या उन्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को वर्ष 1993 में प्रस्तुत कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार इस पर कब तक निर्णय करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) बाण सागर परियोजना 1978 में शुरू की गई थी।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1980 में गठित सोन नदी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सोन नदी बेसिन की कुल जल क्षमता (योल्ड) भी दर्शाई गई थी।

(ग) सभी बेसिन राज्यों के सहमत न होने के कारण अतिरिक्त जल के आबंटन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका।

चंबल जल परियोजना का निर्माण

1853. **श्री चुन्नी लाल चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आगरा की वाह तहसील में चंबल नदी पर "चंबल जल परियोजना" निर्माणाधीन है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश की सहमति मांगी गई है क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी है जो दोनों राज्यों से हो कर बहती है;

(ग) क्या यह सच है कि जो क्षेत्र इस परियोजना द्वारा सिंचित होगा, उस क्षेत्र में सिंचाई की कोई अन्य व्यवस्था व्यवहार्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिए केवल तकनीकी और निवेश स्वीकृति देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने "चम्बल जल परियोजना" नाम से कोई परियोजना स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत "चम्बल लिफ्ट योजना", उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अन्तर राज्यीय पहलुओं का समाधान न होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई है।

बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को लाभ

1854. **श्री चुन्नी लाल चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सरकारों के बीच कनहर परियोजना पर बाणसागर समझौता हुआ था, यदि हां, तो उपरोक्त समझौते के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा कितना जल उपयोग किया जाना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कनहर नदी पर प्रस्तावित बांध बनाये जाने की परियोजना निर्माणधीन है; और

(ग) यदि हां, तो बांध के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सितम्बर, 1973 में हुए बाणसागर परियोजना समझौते के अनुसार, उत्तर

प्रदेश सोन के 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग कर सकता है।

(ख) और (ग) अन्तरराज्यीय एवं अन्य मामलों का निपटान न होने के कारण केन्द्र सरकार ने इस परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 1998 तक इस परियोजना पर 40.92 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य सोन नदी के जल का बंटवारा

1855. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने वर्ष 1973 में सोन नदी के जल के बारे में एक समझौता किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने नदी के कुल जल का आकलन 16.37 एस०ए०एफ किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जल के बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य क्रमशः 1.25, 7.5 और 5.25 एस०ए०एफ० की मात्रा पर सहमति हुई थीं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद भी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय न करने से यह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित किए गए सोन नदी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्द्रापुरी में सोन बेसिन की पैदावार 75% विश्वसनीयता पर 16.37 मिलियन एकड़ फुट दिखाई गई थी।

(ग) समझौते के अनुसार उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए जल का आबंटन क्रमशः 1.25, 7.75 और 5.25 मिलियन एकड़ फुट है।

(घ) जी, नहीं। तथापि सभी बेसिन राज्यों के सहमत न होने के कारण सोन नदी आयोग द्वारा आकलित अतिरिक्त जल का आबंटन नहीं किया गया है।

Recommendations by Dr. Alagh Committee on Cauvery Water Dispute

1856. SHRI S. M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether his Ministry have gone into the recommendations given by Dr. Alagh Committee set up regarding Cauvery water dispute; if so the details of such study including the reaction thereto;

(b) whether Government have agreed to implement the recommendations of the said Committee; and

(c) what are the salient points of Dr. Alagh Committee report and specific amongst them from practical point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Ministry of Water Resources appointed an Expert Group on 2nd January, 1996 comprising of Dr. Y.K. Alagh, Dr. Bharat Singh and Mr. S.P. Caprihan for an On-the-Spot Assessment of the standing crops in the Mettur Ayacut area of Tamil Nadu and Cauvery Ayacut area in Karnataka in connection with suit filed by Tamil Nadu in December, 1995 in the Supreme Court. The Expert Group submitted its report on 19th January, 1996 to Ministry of Water Resources. The main recommendations *inter-alia* contained in the report are as below:—

(i) Keeping in view, the shortage of water in both States, Karanataka must ensure availability of 11.4 TMC of water as due to Tamil Nadu from January to May.

(ii) However, to mitigate the problem of shortage in Tamil Nadu particularly in the months of January February and March when the demand will be at peak, the availability during these months may be augmented so as to enhance availability at Mettur Dam of an additional